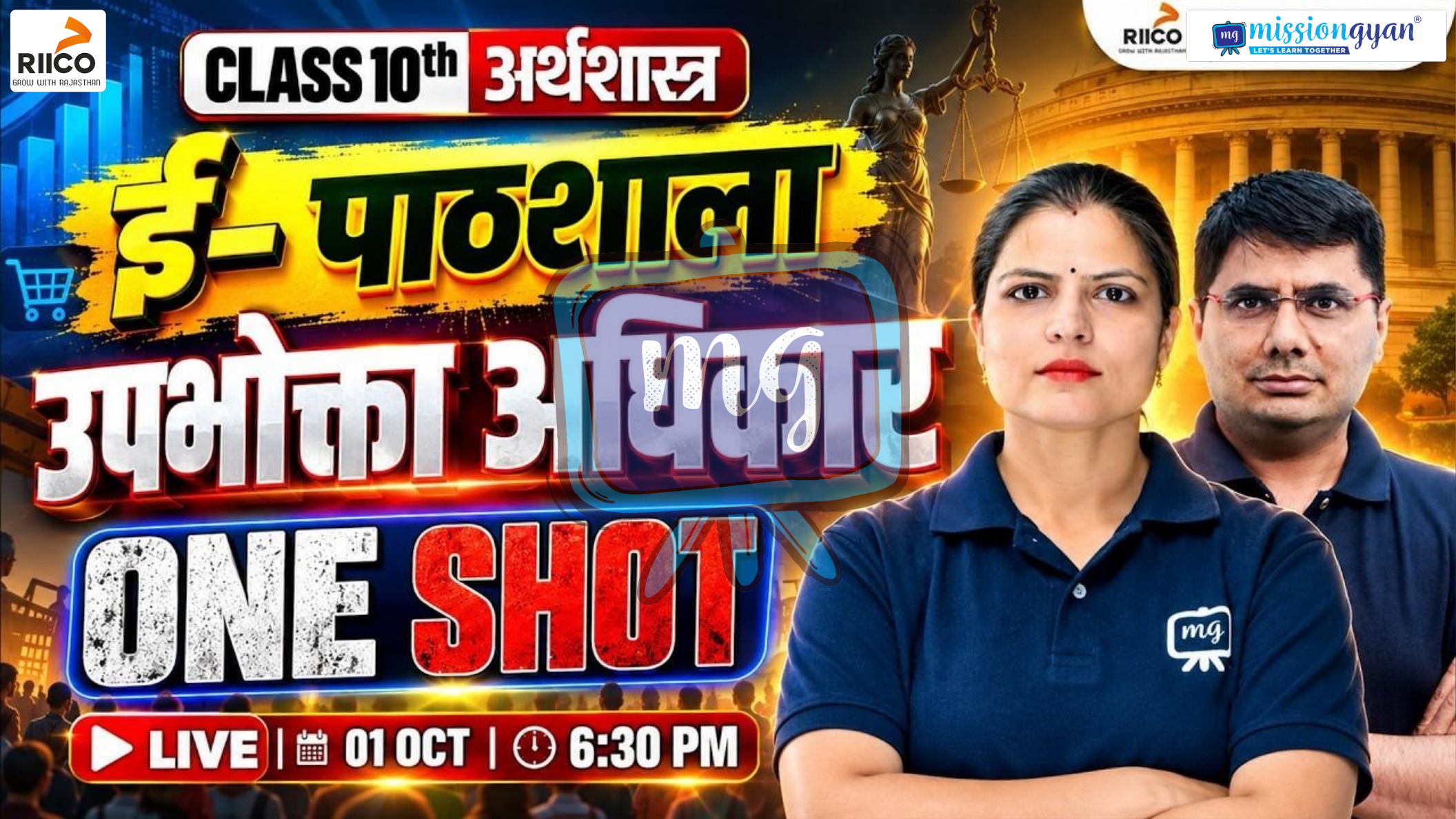
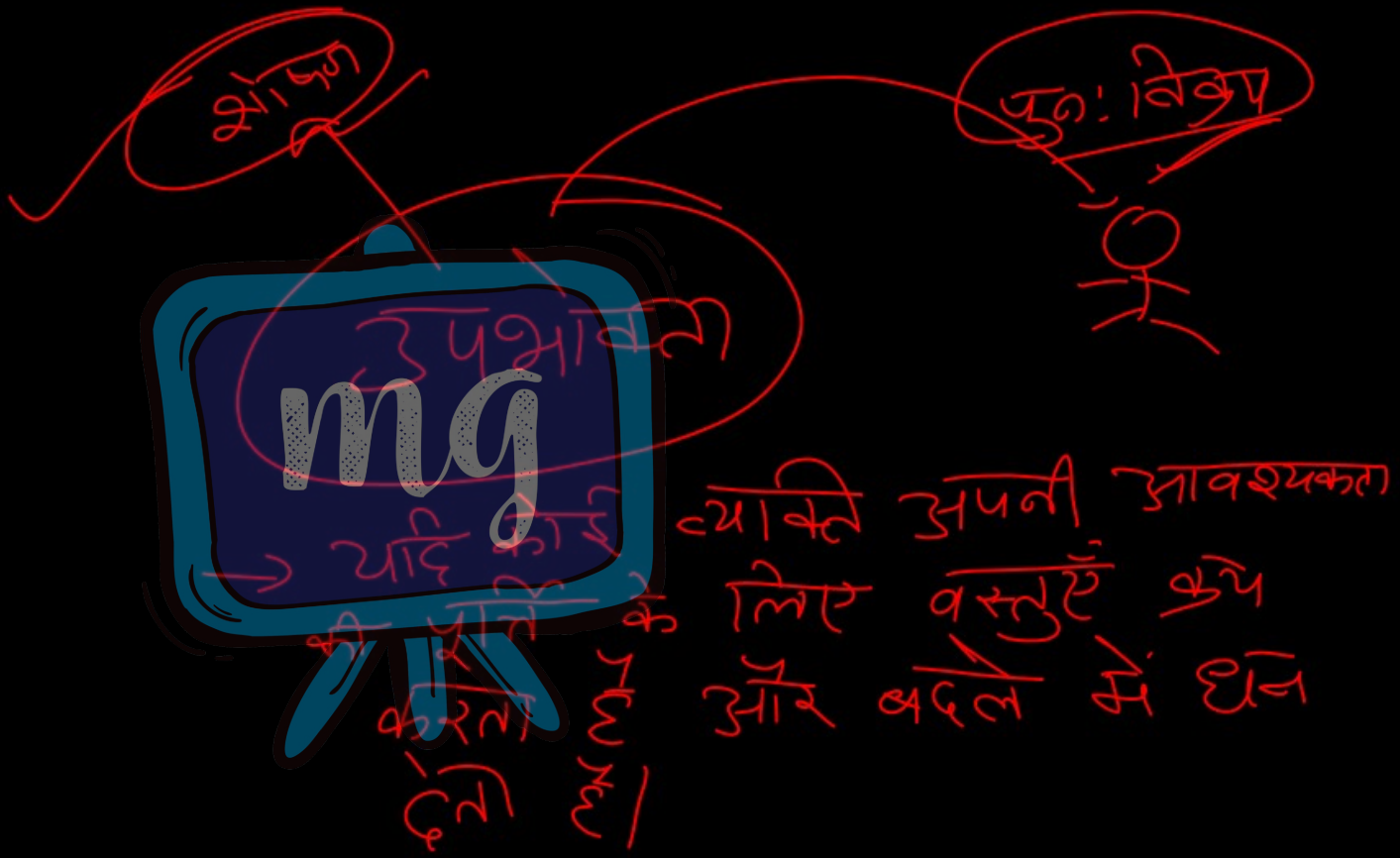

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN
CLASS 10th अर्थशास्त्र
ई-पाठशाला
उपभोक्ता अधिकार
ONE SHOT
LIVE | 01 OCT | 6:30 PM
RIICO
missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

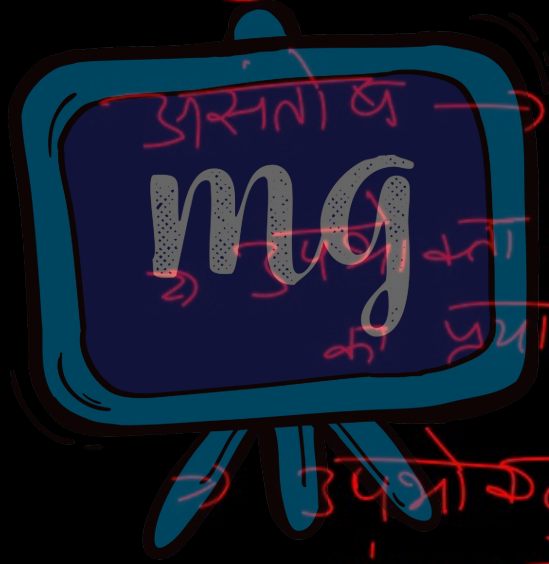
missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER



# उपभोक्ता शोषण



# उपभोक्ता आंदोलन



1960 के दशक

असंतोष → विरोध → आंदोलन

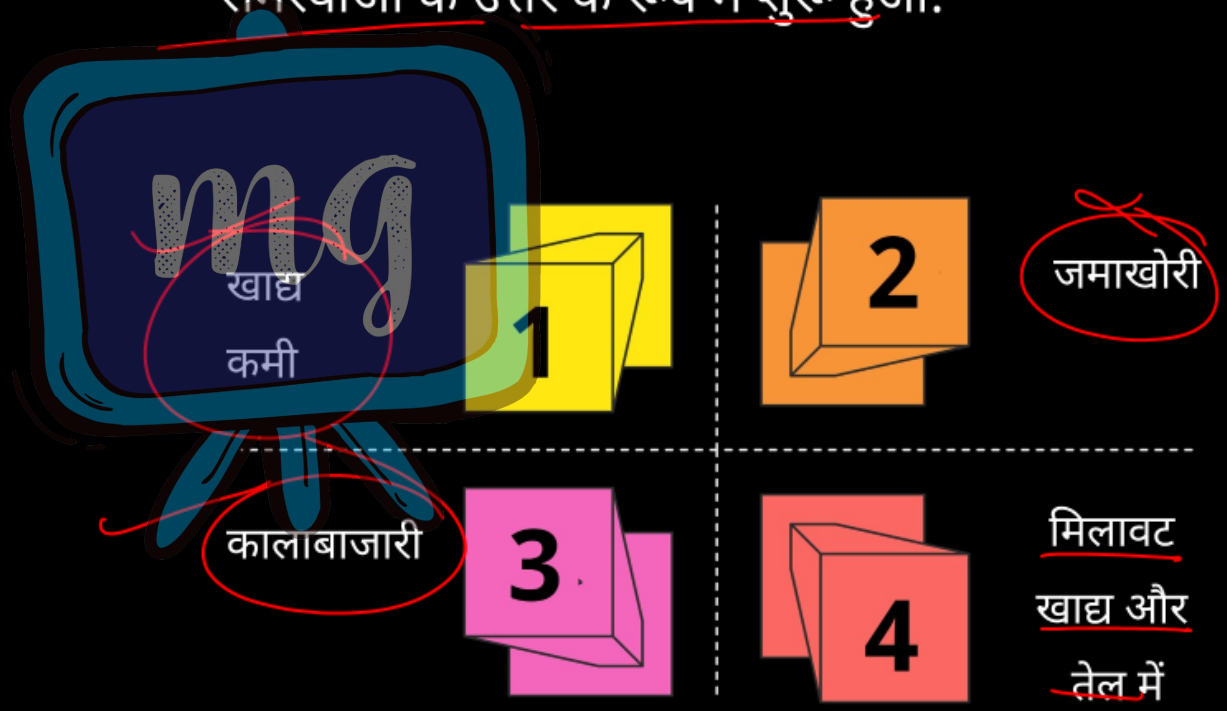
उपभोक्ता को शोषण से बचाने का प्रयास

उपभोक्ताओं के लिए कानूनों का लाने प्रयास

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

☛ भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में इन समस्याओं के उत्तर के रूप में शुरू हुआ:—



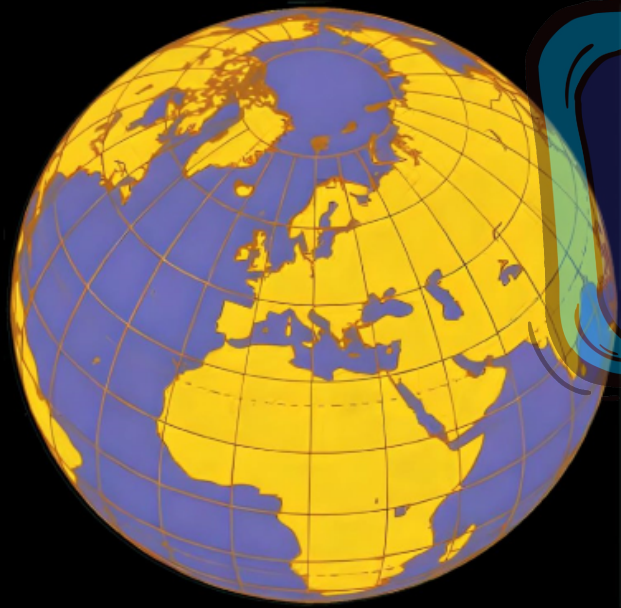
- एक महत्वपूर्ण विकास 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ("COPRA") का लागू होना था।



RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

# उपभोक्ता इंटरनेशनल



- 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के दिशा-निर्देश अपनाए।
- उद्देश्य
  - यह ऐसा साधन था जिसे देश उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए अपना सकते थे।
  - उपभोक्ता पक्षधर समूह अपनी सरकारों पर कानून बनाने का दबाव डाल सकते थे।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER




- सुरक्षा का अधिकार
- सूचित होने का अधिकार
- चुनने का अधिकार
- निवारण पाने का अधिकार
- प्रतिनिधित्व का अधिकार

# 1. सुरक्षा का अधिकार

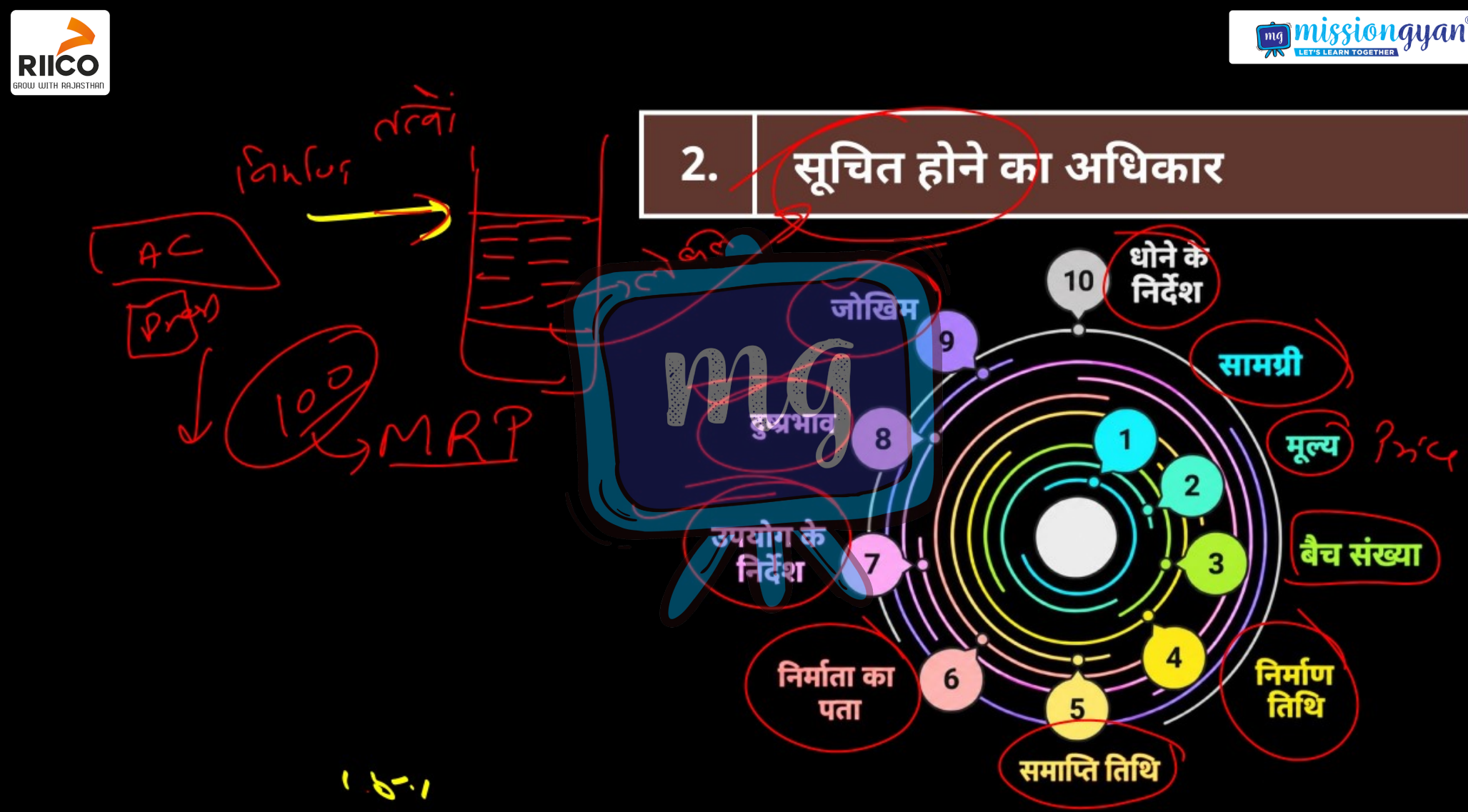


→ वस्तु / सेवा से होने वाली
क्षति शारीरिक, मानसिक,
आर्थिक हानि से सुरक्षा
प्राप्त करना।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

## 2. सूचित होने का अधिकार

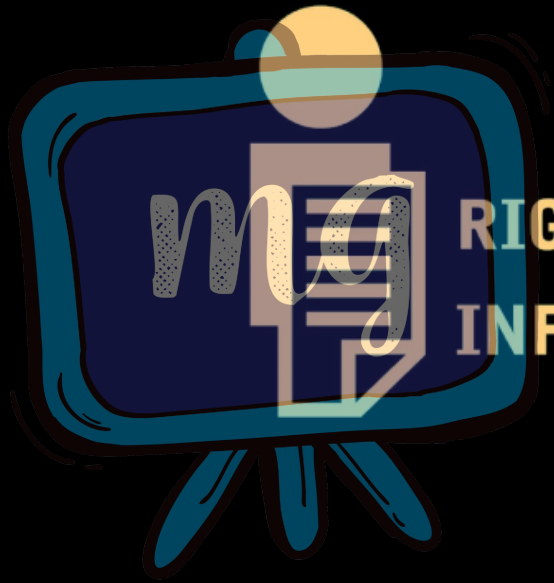


RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

# सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI)

2005 Act



RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

# 3. चुनने का अधिकार




उपभोक्ता को किसी भी वस्तु की आवश्यकता वह उसी वस्तु को प्राप्त/चयन करता है। उसी वस्तु के लिए धन भी देता है।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

# 4. निवारण पाने का अधिकार



→ किसी वस्तु से यदि उपभोक्ता को क्षति पहुंचाती होती है तो वह इसके लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

निम्नलिखित

# 5. प्रतिनिधित्व का अधिकार



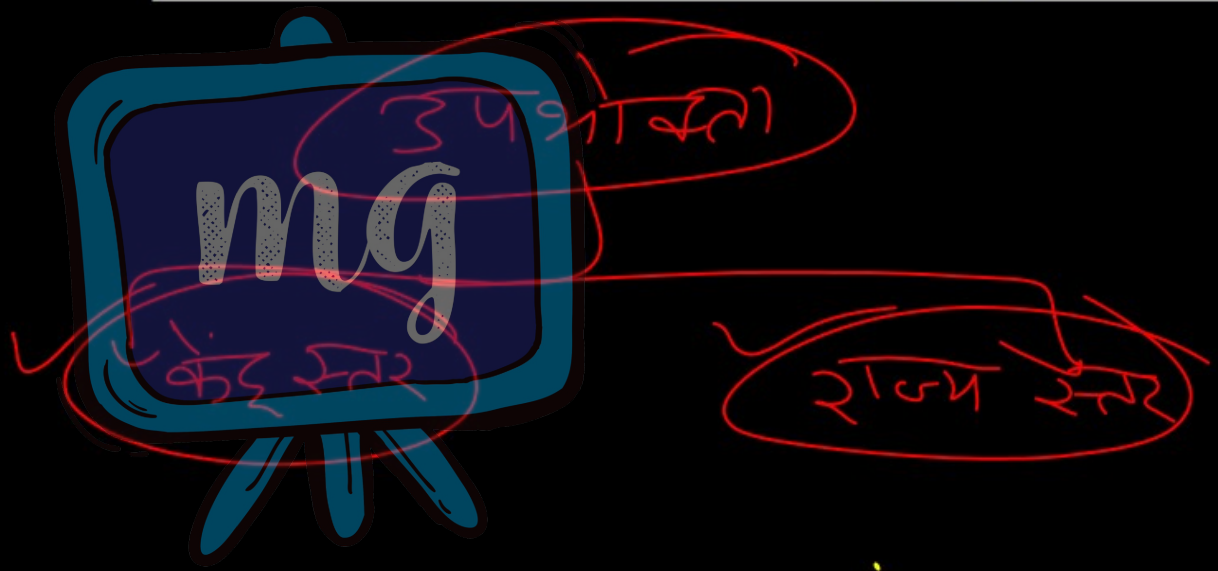

उपभोक्ता → समूह/संघ/परिषद

# उपभोक्ता शिकायतों का आधुनिकीकरण




- ऑनलाइन शिकायतें
- मामले की कार्यवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- सामूहिक वाद दायर करने का विकल्प

# उपभोक्ता अधिकारों के लिए सरकारी सहयोग



# जागरूकता अभियान



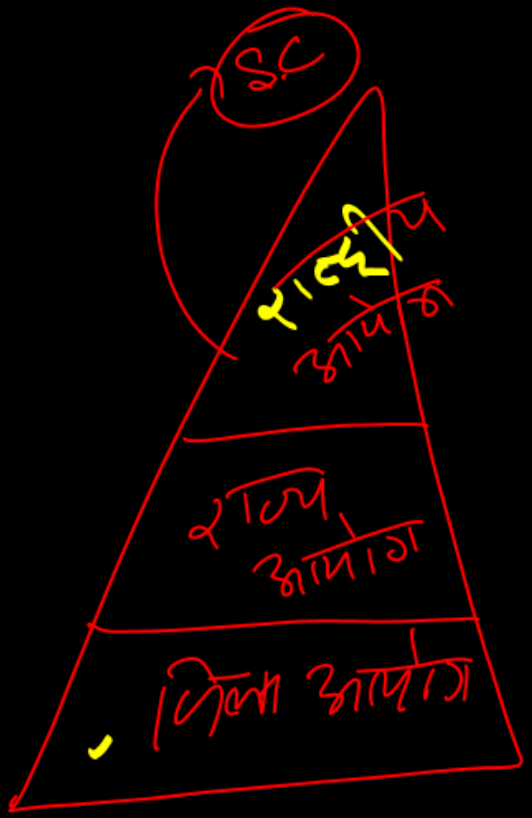
→ कोई वस्तु लेने पर बिल

→ वस्तु से संबंधित जानकारी/सूचनाएं

→ पोस्टर/विज्ञापनों के माध्यम से अधिकारों के बारे जागरूक

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER




# उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–1986 (COPRA)

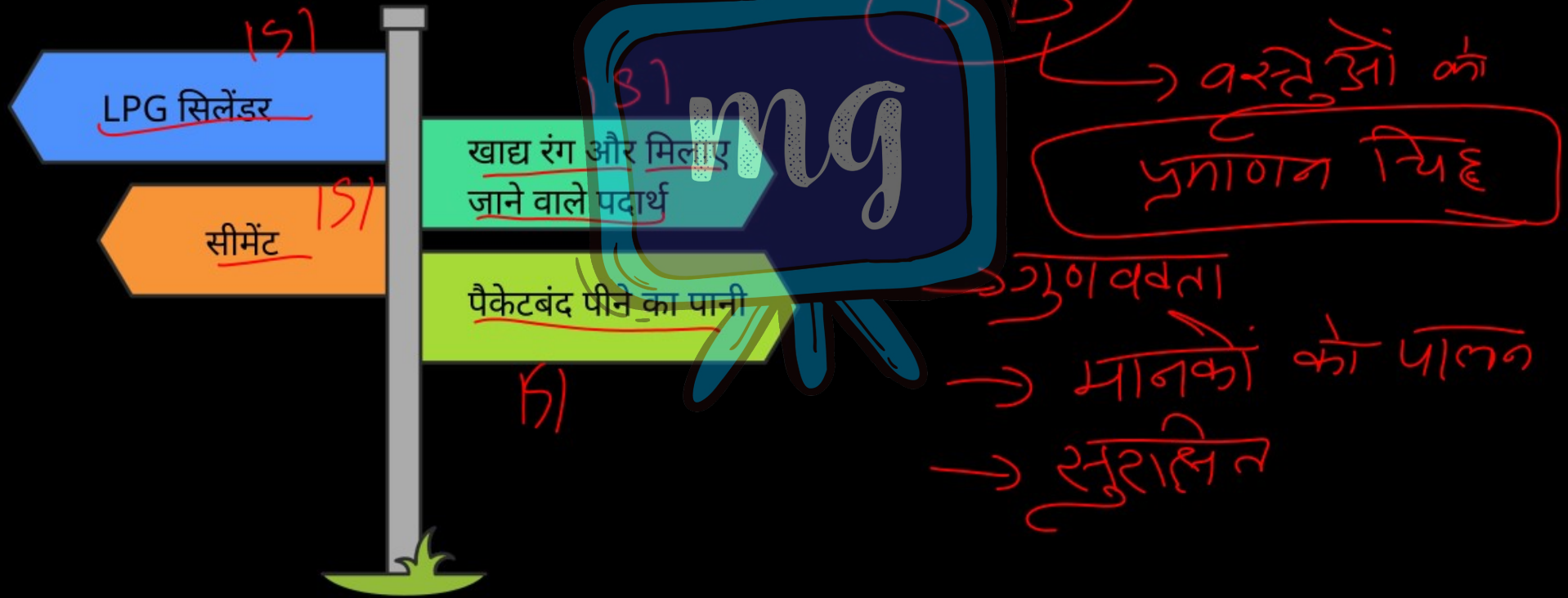
इसने उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए तीन-स्तरीय अर्ध-न्यायिक व्यवस्था स्थापित की।

| राष्ट्रीय आयोग | राज्य आयोग | जिला आयोग |
|---|---|---|
| 10 करोड़ से अधिक | 1 करोड़–10 करोड़ | 1 करोड़ से कम |

# COPRA संशोधन (2019)



# ISI और AGMARK



RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



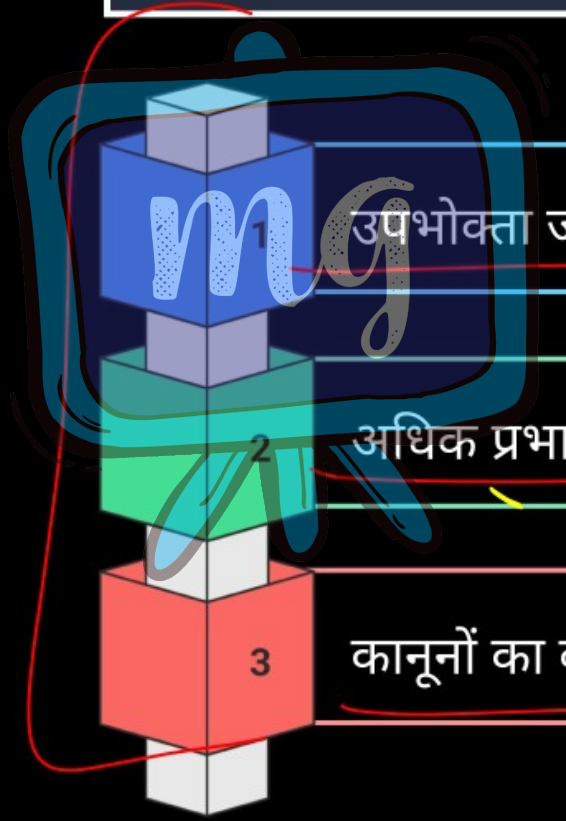

- केवल कुछ ही अच्छी तरह संगठित हैं
- धीमी और महँगी प्रक्रिया
- उचित दस्तावेजों का अभाव
- जागरूकता का अभाव
- नियमों का पालन नहीं होता

# भारत में उपभोक्ता आंदोलन की चुनौतियाँ




1) असंगठित
2) जागरूकता का अभियान

# बेहतर उपभोक्ता संरक्षण के उपाय



1. उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि
2. अधिक प्रभावी निवारण व्यवस्था
3. कानूनों का कड़ा पालन

Q1) उपभोक्ता के 2 अधिकार बताएं।

→ सूचना, चयन

Q2) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष

→ 1986

Q3) COPRA संशोधित होकर किस वर्ष

→ 2019

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

mg missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

Q4) उपभोक्ता के लिए कितने स्तर पर अर्द्ध-न्यायिक व्यवस्था?
⇒ 3

Q5) जिला आयोग ⇒ 1 करोड़ या उससे कम

Q6) राष्ट्रीय ~~आयोग~~ ⇒ 10 करोड़ या इससे अधिक

Q7) 1986 में ~~उपभोक्ताओं~~ को शोषण से बचाने के लिए किसने दिशा निर्देश दिए?
⇒ UN